प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का योगदान

शोधार्थी
दीपक कुमार दास
राजनीति विज्ञान विभाग
सिदो–कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय,दुमका

(बीज शब्द : कौशल विकास ,युवा ,रोजगार, प्रशिक्षण, प्रभाव, सरकार की भूमिका)

सारांश

विकसित भारत के निर्माण की दिशा में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)एक अनूठी पहल है, जिसका आरंभ मेक इन इंडिया के तहत किया गया है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को सार्थक उद्योग तथा कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना है। वास्तव में भारत की आधी से अधिक आबादी युवा है और लगभग 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण है जहां कौशल प्रशिक्षण का अभाव देखने को मिलता है । यह शोध आलेख पीएमकेवीवाई के प्रभाव एवं महत्व का संक्षिप्त अध्ययन है, जिसमें यह जानने का प्रयास किया गया है कि यह योजना युवाओं के कौशल विकास में क्या योगदान कर रहा है।

भारत के युवाओं में कौशल का विकास करने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को विभिन्न कार्यों में सक्षम बनाकर देश में रोजगार लाना है। इस योजना को मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंट्रेप्रेनशिप द्वारा नियंत्रित और नियमित किया जाता है। इस मंत्रालय का मुख्य काम युवाओं के लिए अवसरों का निर्माण करना है ताकि इन अफसरों में वे अपना पसंदीदा मार्ग चुनकर अपना भविष्य उस मार्ग की सहायता से बना सकें। इस योजना के तहत युवाओं को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाता है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ऐसे युवाओं को लाभ मिलेगा जो दसवीं और बारहवीं करके पढ़ाई छोड़ चुके हैं और उनके पास आगे कोई भी रोजगार नहीं है। कुछ युवा गरीबी के कारण या किसी अन्य कारण से पढ़ाई छोड़ देते हैं, ऐसे युवाओं को यह योजना आगे लेकर आएगी ताकि ऐसे युवाओं को ट्रेनिंग दी जाए और उनको रोजगार में मदद की जाए। ट्रेनिंग के बाद इन युवाओं को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा ताकि आगे रोजगार प्राप्त करने में यह उनकी सहायता करें। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अनुसार सभी युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा ।यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके।

इस योजना की खास बात यह है कि जो छात्र प्रशिक्षण के दौरान अच्छा प्रदर्शन करेंगे उन्हें नगद इनाम भी दिया जाएगा जिससे वह ओर प्रेरित हो सकें। इस योजना के तहत 49 प्रतिशत रोजगार दर में वृद्धि हुई है। इस योजना के तहत आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करना है जिसके अंतर्गत वह गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त कर पाएंगे। वह अपना खुद का बिजनेस खोल सकते हैं जिसके लिए केंद्र सरकार भी मदद करेगी।

इस योजना के तहत मोबाइल कंपनियॉ योजनाओं से जुड़े लोगों को मैसेज करके एक टोल फ्री नंबर देती है जिस पर कैंडिडेट को मिस कॉल देना होता है। मिस कॉल के तुरंत बाद आपके पास एक नंबर से फोन आएगा जिसके बाद आप आई.भी.आर. सुविधा से जुड़ जाएंगे। इसके बाद कैंडिडेट को अपनी जानकारी निर्देशानुसार भेजनी होगी। आपके द्वारा भेजी गई जानकारी कौशल विकास योजना के सिस्टम में सुरक्षित रख ली जाएगी। यह जानकारी मिलने के बाद आवेदनकर्ता को उसी के क्षेत्र में यानी कि उसके निवास स्थान के आसपास ट्रेनिंग सेंटर में जोड़ा जाएगा जहां से आपको पूरी जानकारी दी जाएगी।

इस योजना के अंतर्गत उम्मीदवार का जो खर्च होगा उसके पैसे सरकार देगी और वह पैसे सीधा ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनिंग सेंटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे इसके लिए सरकार ने कुछ नियम भी बनाए हैं जिसके अंतर्गत हर उम्मीदवार का आधार वैलिडेशन होना जरूरी है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना युवाओं के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत सरकार युवाओं को प्रशिक्षित कर नौकरी मुहैया कराएगी । इसके प्रमुख उद्देश्य निम्न है–

पहला, इस योजना के अंतर्गत सरकार कम से कम देश के 24 लाख युवाओं को विभिन्न तरह के तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षित करना चाहती है, जिसका कुल शुल्क 1500 करोड़ रुपए का है।

दूसरा, देश के युवाओं में कई ऐसे टैलेंट भी हैं जो कारगर है किंतु किसी वजह से लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे है।उन्हें विकसित करने के लिए सरकार कौशल विकास योजना चला रही है।

तीसरा, इस योजना के अंतर्गत पाया गया सर्टिफिकेट समस्त भारत में मान्य होगा।अतः एक न्यूनतम शुल्क के साथ सरकार युवाओं को प्रशिक्षित कर सर्टिफिकेट देगी जिसके आधार पर उन्हें निजी अथवा सरकारी क्षेत्र में नौकरियों प्राप्त हो सकेगी।

चौथा, इस योजना के तहत युवाओं को उत्कृष्ट स्तर का अनुभव विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि उन्हें उनके चयनित क्षेत्र संबंधी हर तरह का ज्ञान हो सके।

पांचवा, कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार प्राप्त करवाना है।

छठा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अनुसार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 2022 तक सभी युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए परंतु यह तभी संभव है जब उनको कौशल के अनुसार ट्रेनिंग दी जाएगी। यह ट्रेनिंग उनको नए रोजगार की तरफ ले जाएगी।

सातवां, इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के सभी युवाओं को प्रोत्साहित करके उन्हें उद्योगों से जुड़े प्रशिक्षण प्रदान करना है जिससे उन्हें रोजगार पाने में मदद मिल सके। इस योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग फीस का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है।सरकार इस स्कीम के जरिए कम पढ़े–लिखे या 10 वीं,12 वीं ड्रॉपआउट(बीच में स्कूल छोड़ने वाले) युवाओं को कौशल विकास योजना के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है।

आठवां, इस योजना के लिए कोई फीस नहीं चुकानी पड़ती है बल्कि बतौर पुरस्कार राशि करीब ₹8000 सरकार देती है।

नौवां, इस योजना में 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। कोर्स पूरा करने के बाद ही सर्टिफिकेट दिया जाता है। यह सर्टिफिकेट पूरे देश में मान्य होगा।

दसवां, अगला इस योजना के तहत ट्रेंड होने वाले युवाओं को ट्रेनिंग के लिए सबको इंडस्ट्री में भेजा जाता है और उन्हें एक्सपर्ट लोगों के अंदर काम करने का मौका मिलता है। जिसके अंतर्गत उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है और इसी के तहत वह अच्छी नॉलेज लेकर अच्छे से अच्छा जॉब हासिल कर सकता है।

ग्यारहवां, इस योजना के अनुसार अलग–अलग योजनाओं के अंतर्गत जितने कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है उतने को ही ट्रेनिंग दी जाती है।

बारहवां, यहां से ट्रेनिंग पूरा कर लेने के बाद ट्रेनिंग लिए हुए लड़कों को अलग–अलग सरकारी योजनाओं में जैसे स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया आदि में खाली जगहों में नौकरी दी जाती है।

इस योजना के तहत कराई जाने वाली सभी तरह की ट्रेनिंग बहुत ही संजीदगी से कराई जाती है। विभिन्न क्षेत्रों में ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए विभिन्न योग्यताओं की आवश्यकता होती है। अतः किसी भी तकनीकी क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने से पहले योग्यता की जांच की जाती है।

सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम का निर्वाहन सेक्टर स्किल काउंसिल यानी (एस.एस.सी)द्वारा किया जाएगा। इस काउंसिल के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाएगा प्रशिक्षण के बाद युवाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे मेक इन इंडिया योजना, डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट, स्वच्छ भारत अभियान आदि के अंतर्गत नौकरी दी जाएगी । एक बार प्रशिक्षण खत्म हो जाने पर प्रशिक्षित युवाओं को ₹800 और कोर्स कंपलीशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यह सर्टिफिकेट सभी जगहों पर मान्य होगा किंतु इसे प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण के अंत में दिए जाने वाले परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। इस योजना की विशेष बात यह है कि इस योजना का ब्रांड मिस्टर सचिन तेंदुलकर है। वे भारतीय युवाओं के लिए आदर्श के रूप में है। अतः युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन को चुना गया है।

कैबिनेट के द्वारा इस योजना के लिए 120 बिलियन का फंड प्रस्ताव किया गया था जिसमें से एक करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की विशेष परियोजना घटक में एक मंच के निर्माण की परिकल्पना की गई है जो विशेष क्षेत्रों या सरकारी निकायों,निगमों ने किया उद्योग निकायों के परिसर में प्रशिक्षण और विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

सरकार द्वारा इस योजना के लिए कुल 15 सौ करोड़ रूपए का फण्ड एलोकेट किया है। इस फंड की सहायता से 24 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस फंड का इस्तेमाल जिन विभिन्न क्षेत्रों में अब तक किया गया है उससे अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं।

पहले सीखने वाले युवाओं को पहचान करके उनके ऊपर विशेष ध्यान देने के लिए लगभग 220 करोड रुपए खर्च किया जाएगा। लगभग ₹67 करोड़ का खच योजना को संचालन और युवाओं को इस डेवलपमेंट के तहत जागरूक करने के लिए किया जाएगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए ₹150 करोड़ आवंटन किया गया है। इस तरह से बाकी फंड का प्रयोग भी सरकार आने वाले समय में आवश्यक युवा कल्याणकारी क्षेत्रों में करेगी।

भारत सरकार देश में बेरोजगारी को समाप्त कर देश को निर्माता के तौर पर वैश्विक केंद्र बनाना चाहती है और यह तभी संभव है जब यहां पर निर्माण कार्य करने जैसी प्रतिभा मौजूद हो। सरकार ने साल 2014 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का गठन किया था। इसके लिए सरकार ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का गठन किया है।

पीएमकेवीवाई युवाओं के कौशल आधारित प्रशिक्षण हेतु एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में विकसित किया गया है। जिससे ना केवल युवाओं में कौशल विकास हुआ है बल्कि इससे गरीबी और बेरोजगारी की समस्या के समाधान की दिशा में बल मिला है। इस योजना द्वारा व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास के कई बड़े राष्ट्रीय कार्यक्रमों को लागू किए गए हैं। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि कौशल विकास आज के युवाओं द्वारा आवश्यक बुनियादी कौशल को संशोधित कर रहा है। यह योजना उद्देश्यपूर्ण तरीके से काम कर रहा है और यह विभिन्न सरकारी योजनाओं की सर्वश्रेष्ठ योजनाओं में से एक है।

जिस प्रकार इस योजना को आरंभ किया गया है वह सराहनीय है और यह दर्शाता है कि सरकार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि कौशल विकास एक मूलभूत पात्रता प्राप्त प्राप्त करने के बाद ही हो सकता है जो सिर्फ स्कूली शिक्षा से मिलता है। इसलिए यह आवश्यक है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि आधार–निर्माण के वर्ष मूल्यवर्धन करते हो और इसके लिए देश भर में प्रारंभिक और प्राथमिक शिक्षा को मजबूती प्रदान की जाए। यह वास्तव में कौशल भारत के स्वप्न को साकार करने में बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है।

संदर्भ

1.http://en.m.wikipedia.org/wiki/skill_India

2.http://pradhanmantri-yogana.in/pradhan-mantri-kaushal-vikas-yojana/

3.https://pmkvyofficial.org/

4.https://www.hindiyojana.in/pradhan-mantri-kaushal-vikas-yojana-in-hindi/

5.https://www.google.com/amp/s/m.economictimes.com/topic/PMKVY/amp

6.https://www.msde.gov.in

7.https://www.startupindia.gov.in/content/sih/en/government-schemes/pmkvy_scheme

8.www.deepawali.co.in/pm-kaushal-vikas-yojana-skill-development-scheme-in-hindi

9.www.deepawali.co.in/pm-kaushal-vikas-yojana-skill-development-scheme-in-hindi

10.Ministry of Skill Development And Entrepreneurship-annual Report 2019

11.PMKVY Guidelines (2016-2020)

12.Special Project Guideline (w.ef.january,2017)